ईयू ग्रीन डील क्यों मायने रखती है

लेखक -अमिताभ सिन्हा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

21 दिसम्बर, 2019

"जहाँ वैश्विक जलवायु वार्ता अपने प्रमुख उद्देश्यों तक पहुँचने में विफल रही है वहीं यूरोपीय संघ अब एक नयी जलवायु कार्रवाई योजना के साथ सामने आया है। इस आलेख में हम जानेंगे कि यूरोपीय संघ की योजना क्या है, यह दूसरी योजना से कैसे भिन्न है और अभी तक इसमें कितनी कार्यवाई की जानी शेष है?"

पिछले हफ्ते मैड्रिड में वार्षिक जलवायु वार्ता एक निराशाजनक परिणाम के साथ समाप्त हुई। न तो यह पेरिस समझौते के तहत् स्थापित किए जाने वाले एक नए कार्बन बाजार के नियमों को परिभाषित करने में सफल हुई ना ही यह अगले साल तक जलवायु क्रियाओं के पैमाने को बढ़ाने के लिए देशों को मनाने में सक्षम हुई। वैज्ञानिक आकलन के मद्देनजर बार-बार की जा रही माँग से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के मौजूदा प्रयास पर्याप्त नहीं थे।

यूरोपीय ग्रीन डील (जलवायु-तटस्थता) 2050

चर्चा में क्यों?

- यूरोपीय संघ के नेताओं ने स्पेन के मैड्रिड में COP 25 सम्मेलन के दौरान 2050 तक जलवायु-तटस्थता हासिल करने पर एक ठोस समझौते पर पहुँचने का दावा किया है।
- इस सौदे का उद्देश्य एक व्यापक रणनीति दस्तावेज बनाना है, जो यूरोपीय संघ की 2050 में ग्रीनहाउस गैसों का समग्र उत्सर्जन न करने की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है

जब यह बैठक जारी थी, तो यूरोपीय संघ, जिसके 28 सदस्य देश चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में ग्रीनहाउस गैसों के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक हैं, जलवायु परिवर्तन पर अतिरिक्त उपायों पर एक घोषणा के साथ सामने आए। इसका नाम यूरोपीय ग्रीन डील दिया गया है, यूरोपीय संघ की घोषणा को एक बड़े कदम के रूप में स्वीकार किया गया था, भले ही इसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव बनाने के लिए अन्य देशों के पूरक प्रयासों की आवश्यकता हो।

दो प्रमुख निर्णय

दो प्रमुख फैसले यूरोपीय ग्रीन डील के केंद्र में हैं। जिसमें से पहला 'जलवायु तटस्थता' प्राप्त करने के बारे में है। यूरोपीय संघ ने 2050 तक 'जलवायु तटस्थ' बनने के लिए सभी सदस्य देशों के लिए एक कानून लाने का वादा किया है। जलवायु तटस्थता, जिसे कभी-कभी शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की स्थिति के रूप में भी व्यक्त किया जाता है और यह तब प्राप्त होता है जब देश का उत्सर्जन वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से संतुलित होता है। वनों की तरह अधिक कार्बन सिंक बनाकर अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है, जबकि हटाने में कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

पिछले कुछ महीनों में, कई देशों द्वारा 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध होने की माँग बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सितंबर में महासभा सत्र के मौके पर एक विशेष बैठक बुलाई थी ताकि इस लक्ष्य के प्रति देशों को प्रतिबद्ध किया जा सके।

60 से अधिक देशों ने अपने जलवायु कार्यों या 2050 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन ये सभी अपेक्षाकृत छोटे उत्सर्जक देश थे। यूरोपीय संघ अब 2050 जलवायु तटस्थता लक्ष्य से सहमत होने वाला पहला सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है। उसने कहा है कि वह इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय कानून पर अगले साल मार्च तक एक प्रस्ताव लाएगा।

दूसरा निर्णय इसके 2030 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य में वृद्धि से संबंधित है। पेरिस समझौते के तहत् घोषित अपनी जलवायु कार्य योजना में यूरोपीय संघ 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की कमी करने के लिए प्रतिबद्ध था। अब इस कमी को कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और 55 प्रतिशत की दिशा में कम करने का वादा किया गया है।

यहाँ तक कि 40 प्रतिशत पर, यूरोपीय संघ के विकसित देशों के बीच सबसे महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य थे। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने 2005 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन में 26-28 प्रतिशत की कटौती करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन पेरिस समझौते से हटने के बाद, यह उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब बाध्य नहीं है।

उत्सर्जन में कटौती के लिए 1990 की आधार सीमा को बनाए रखने के लिए यूरोपीय संघ भी प्रमुख उत्सर्जकों में से एक है, मूल रूप से सभी विकसित देशों के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत् यह अनिवार्य है। अधिकांश अन्य देशों ने अपने बेसलाइन को 2005 या 2015 के पेरिस समझौते के तहत् स्थानांतरित कर दिया है।

यूरोपीय संघ का 2050 लक्ष्य

- यूरोपियन ग्रीन डील के एलान के बाद हुआ ये पहला सम्मेलन था। इस डील के मुताबिक वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसकी कायापलट कर 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है।
- साल 2015 में पेरिस में जलवायु समझौता हुआ था। उसमें 2050 को ध्यान में रखा गया था। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को जीवाश्म ईंधनों की वजह से हो रहे कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा और इन ईंधनों का विकल्प भी तलाशना होगा।
- ये विकल्प ऐसे होंगे जो किसी तरह का प्रदूषण न फैलाएं। फिलहाल पोलैंड ने इस समझौते में शामिल होने से इंकार कर दिया।
- इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है दरअसल पोलैंड में 80 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन कोयले की मदद से होता है। पोलैंड ने फिलहाल खुद को इस समझौते से बाहर रखा है।

क्यों हुआ पोलैंड बाहर

- पोलैंड की अर्थव्यवस्था अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 80% कोयले पर निर्भर करती है। इसने योजना का विरोध किया और उत्सर्जन में कटौती के लिए 2070 तक की अवधि बढ़ाने के लिए कहा।
- अन्य देशों ने पोलैंड की शर्तों के साथ जाने से इंकार कर दिया। इसलिए, पोलैंड को अपने रास्ते पर जलवायु तटस्थता तक पहुँचने की उम्मीद है।

ग्रीन डील में इन दो समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय योजनाएँ और नीतिगत बदलावों के प्रस्तावों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, इसमें 2030 तक इस्पात उद्योग को कार्बन-मुक्त बनाने, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए नई रणनीति, रेलवे के प्रबंधन में संशोधन और उन्हें अधिक कुशल बनाने के साथ-साथ वाहनों के लिए अधिक कठोर वायु प्रदूषण उत्सर्जन मानकों का प्रस्ताव शामिल करना होगा।

दूसरों से बेहतर

यूरोपीय संघ, उत्सर्जन को कम करने पर अन्य विकसित देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 2010 में, यूरोपीय संघ ने 1990 के स्तर से 2020 तक अपने उत्सर्जन को कम से कम 25 प्रतिशत कम करने का वादा किया था। 2018 तक, उसने उत्सर्जन में 23 प्रतिशत की कमी हासिल करने का दावा किया है। उत्सर्जन में कमी के संदर्भ में यह संभवतः यूरोपीय संघ के बाहर किसी भी विकसित देश के विपरीत, 2020 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने ट्रैक पर है।

कनाडा, जो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर चला गया है, ने पिछले साल बताया था कि 2005 के उत्सर्जन से इसका उत्सर्जन 4 प्रतिशत कम था, लेकिन 1990 की तुलना में, यह लगभग 16 प्रतिशत अधिक था। जापान, जो क्योटो प्रोटोकॉल का परित्याग करने वाला एक अन्य देश है, ने कहा कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसका उत्सर्जन 2013 आधार सीमा के नीचे लगभग 8 प्रतिशत पर आ गया है, लेकिन 1990 के स्तर की तुलना में यह मामूली कमी है।

हालाँकि, यूरोपीय संघ भी अपने सभी जलवायु दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार अमीर और विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करना था। इस संदर्भ में, विशेष रूप से विकासशील देशों के अनुकूलन की जरूरतों के लिए यूरोपीय संघ से बहुत सहायता प्रदान की गई है, साथ ही नई जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को पेटेंट और स्वामित्व जटिलताओं में बदल दिया गया है।

आगे की राह

ग्रीन डील महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उत्सर्जन में कमी को प्राप्त करने के लिए अपने आप में अपर्याप्त है। चीन और भारत जैसे बड़े विकासशील देशों सहित अन्य बड़े उत्सर्जकों की ओर से इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि वे अपनी जलवायु क्रियाओं पर तत्काल अंकुश लगाने पर विचार कर रहे हैं।

समझौते की घोषणा करते हुए, यूरोपीय संघ ने अन्य देशों से भी अपने कार्यों की महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाने का आग्रह किया है। "जब तक कई अंतरराष्ट्रीय साझेदार यूरोपीय संघ के समान महत्त्वाकांक्षा साझा नहीं करते हैं, तब तक कार्बन रिसाव का खतरा होता रहेगा, क्योंकि या तो उत्सर्जन में कमी के लिए उत्पादन को यूरोपीय संघ से दूसरे देशों में कम महत्त्वाकांक्षा के साथ स्थानांतरित किया जाएगा, या यूरोपीय संघ के उत्पादों को अधिक कार्बन-गहन आयात द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यदि यह जोखिम बढ़ जाता है, तो वैश्विक उत्सर्जन में कोई कमी नहीं होगी और यह पेरिस समझौते के वैश्विक जलवायु उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ और इसके उद्योगों के प्रयासों को निराश करेगा।"

नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है?

- नेट जीरो एमिशन का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल ना के बराबर हो, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल एक दम कम हो, जिन चीजों से कार्बन उत्सर्जन होता है उसे सामान्य करने के लिए कार्बन सोखने के इंतजाम भी साथ में किए जाएँ।
- नेट जीरो एमिशन का मतलब एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें कार्बन उत्सर्जन का स्तर लगभग शून्य हो। इसकी वजह आईपीसीसी द्वारा की गई एक भविष्यवाणी है।
- इसके मुताबिक आने वाले सालों में अगर ठोस इंतजाम नहीं किए गए तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाएगा। इस बढ़ोत्तरी को दो डिग्री से कम रखने के लिए नेट जीरो एमिशन जैसी व्यवस्था बेहद जरूरी है।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में मैड्रिड में वार्षिक जलवायु वार्ता एक निराशाजनक परिणाम के साथ समाप्त हुई, इस वार्ता में यूरोपीय संघ द्वारा घोषित ग्रीन डील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यूरोप के लिए ग्रीन डील शून्य ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन से संबंधित एक महत्त्वाकांक्षी और व्यावहारिक योजना है।
2. यूरोपीय ग्रीन डील में जलवायु तटस्थता और 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों की कटौती लक्ष्य में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Recently the annual climate talks in Madrid ended with a disappointing outcome, consider the following statements in the context of the Green Deal announced by the European Union in this dialogue:-**

1. he Green Deal for Europe is an ambitious and viable plan for zero greenhouse gas emissions.
2. The European Green Deal emphasizes on climate neutrality and increase the reduction target of greenhouse gases by 2030.

Which of the above statements is/are incorrect?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) None of these

नोट : 20 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: अथक प्रयासों के बावजूद भी निरंतर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ द्वारा लाया गया ग्रीन डील प्रस्ताव ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने में कहां तक उपयोगी सिद्ध होगा? समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)

Despite relentless efforts, the emission of greenhouse gases is continuously increasing. In this context, how far will the Green Deal proposal brought by the European Union prove useful in reducing the emission of greenhouse gases? Comment. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।